हमने 3 वर्षों में 200 अरब लीटर पानी बचाया

'अवना' की युवा CEO मैथिली अप्पलवार द्वारा अहम् जानकारी प्रदान

पुणे, 22 जुलाई (आ.प्र.)

किसानों को मात्र पानी की बचत का संदेश ही नहीं दिया बल्कि उसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराकर उन्हें स्वयं-सहायक बनाने का कार्य महाराष्ट्र व राजस्थान के विभिन्न जिलों में हमने किया. हमने 3 वर्षों में 200 अरब लीटर पानी की बचत की. यह जानकारी 'एम्बी इंडस्ट्रीज' की स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट 'अवना' की 22 वर्षीय संस्थापक सीईओ मैथिली अप्पलवार ने सोमवार को यहां दै.'आज का आनंद' प्रतिनिधि को दी.

मैथिली ने बताया कि बहुलक प्रसंस्करण (पॉलीमर प्रोसेसिंग) क्षेत्र की एम्बी कंपनी पैकेजिंग, एग्रो पॉलीमर व जल संरक्षण सहित चार वर्टिकल्स में कार्यरत है. 57 देशों को यह कंपनी उत्पाद निर्यात कर रही है. उन्होंने बताया कि कृषि व कृषकों के मसले आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए हल कर उन्हें गरीबी से उबारना हमारा उद्देश्य है.

मैथिली अप्पलवार

इसके लिए हम महाराष्ट्र व राजस्थान सरकार के साथ कार्य कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी सरकार ने भी इस साल पानी की बचत का महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया है और हमारा काम इसे ताकत देने वाला है. सिर्फ ढाई लाख रुपये में 40-50 लाख लीटर पानी 5 साल तक स्टोर रखने वाले हमारे उत्पाद हैं तथा जल-संचय हेतु सिर्फ एक पैसा प्रति लीटर खर्च आता है. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में पुणे के अलावा अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड़, सोलापुर, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, जलगांव, बुलढाना, धुलिया, वाशिम, हिंगोली व नासिक तथा राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर व भीलवाड़ा में कुल मिलाकर 200 अरब (बिलियन) लीटर पानी बचाया गया.

उन्होंने बताया कि 'फिश फ्रेंडली पॉण्ड्स' हमारी नई टेक्नोलॉजी है और फिलहाल इसका परीक्षण चल रहा है. यह अगस्त महीने में बाजार में लाई जाएगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर हमने पानी का 30 प्रतिशत इस्तेमाल कम करने की तकनीक भी विकसित की है. कंपनी के पास 15 पेटेंट हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज के सहयोगी ने प्रोडक्ट विकसित किया है. वेयर हाउस में चूहों व घूसों का उत्पात रोकने के लिए रोडेंट रिपेलंट खास प्लास्टिक बनाया गया है.

नवभारत

ज्वैलरी-कपड़ा उद्योग निराश, कृषि क्षेत्र खुश

पूंजी बाजार को भी झटका

व्यापार प्रतिनिधि

मुंबई. उद्योग-व्यापार जगत को मोदी '2.0' के दूसरे बजट से जितनी उम्मीदें थी, उतने प्रोत्साहन तो वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2.40 घंटे के लंबे भाषण में नहीं दिए. बजट में जेम-ज्वैलरी और कपड़ा उद्योग जैसे भारी रोजगार वाले क्षेत्रों को तो निराश किया है. पूंजी बाजार को भी नए टैक्स सिस्टम के विकल्प में आयकर छूट की समाप्ति के प्रस्ताव से बड़ा झटका लगा और बीएसई का बेंचमार्क सेंसेक्स 988 अंकों की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ. बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के साथ उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ाने के उपाय किए गए हैं. उद्योग-व्यापार विशेषज्ञों ने बजट पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है.

किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी : छाबरिया

फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लि. के कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश छाबरिया ने कहा कि वित्तमंत्री ने इस बजट में हमारे देश के किसान बंधुओं और बहनों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर सुधारने के लिए विशेष ध्यान दिया है. क्योंकि किसान ही भारत के मजबूत स्तंभ हैं. किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने पर ही देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी. बजट में 16 सूत्रीय कार्ययोजना प्रस्तावों से वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी. वर्ष 2020 का यह बजट निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा.

उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी : भरतिया

कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा कि यदि बजट की घोषणाएं एक निश्चित समय सीमा में लागू की गई तो निश्चित रूप से यह जहां आय में वृद्धि करेगा, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को भी बढ़ाएगा. बजट घोषणाएं देश में निर्यात को बढ़ाएंगी और भारत वैश्विक बाजार में अधिक हिस्सेदारी हासिल कर सकेगा. बजट में की गई घोषणाएं देश में घरेलू व्यापार और मैनुफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करेंगी.

बुलियन एक्सचेंज की घोषणा सराहनीय : अग्रवाल

जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि यह आम बजट जेम-ज्वैलरी सेक्टर के लिए मिला-जुला रहा है. गिफ्ट सिटी में बुलियन एक्सचेंज शुरू करने की योजना सराहनीय कदम है. 'निर्विक' (निर्यात ऋण विकास) योजना से छोटे निर्यातकों की बीमा लागत घटेगी और कम दरों पर वित्त उपलब्ध होगा. वित्तमंत्री ने प्लेटिनम पर तो आयात शुल्क 12.5% से घटाकर 7.5% कर राहत दी है, लेकिन सोने-चांदी पर ऊंचा आयात शुल्क कायम रखा है.

कठिन हालात में संतुलित बजट : पटेल

आइसमेक रेफ्रिजरेशन लि. के अध्यक्ष चंद्रकांत पटेल ने कहा यह बजट सरकार के हाथ में सीमित संसाधनों के बावजूद काफी संतुलित है, इन कठिन आर्थिक हालात में भी वित्तमंत्री राजकोषीय जिम्मेदारी बनाए रखने में सक्षम हैं और बेंचमार्क के रूप में 10% पर नॉमिनल जीडीपी वृद्धि काफी समझदार और सबसे बड़े सकारात्मक पहलु है. विभिन्न योजना की रूपरेखा में निधि आवंटन में वृद्धि से संकेत मिलता है कि सरकार के निजी निवेश चक्र को पुनर्जीवित करने और कृषि आय बढ़ाने के लिए गंभीर इरादे हैं. जहां तक हमारे कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स इंफ्रा सेक्टर की बात है तो हमारा मानना है कि नए और बढ़े हुए बजट प्लान की वजह से ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा.

किसानों की कमाई बढ़ेगी : मैथिली

एम्बी इंडस्ट्रीज लि. की निदेशक मैथिली अप्पलवार ने कहा कि वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री की वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के विजन के तहत कृषि क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस किया है. कृषि और किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 16 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्ताव निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है. 20 लाख किसानों को सौलर पंप, कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए विशेष ट्रेनें, नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार, स्वयं सहायता समूहों द्वारा ग्राम कृषि भंडारण सुविधाओं की स्थापना जैसे अच्छे कदमों से फल-सब्जियों और कृषि उत्पादों की बर्बादी रूकेगी और किसानों की कमाई बढ़ेगी. वित्तमंत्री ने एग्री के साथ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर के विकास को भी ज्यादा ध्यान दिया है.

स्वर्ण एवं हीरा कारीगरों को सरंक्षण नहीं : शाह

ज्वैलमेकर्स वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय शाह ने कहा कि बजट में जेम एंड ज्वैलरी उद्योग की एक तरह से अनदेखी की गयी है. मंदी से त्रस्त उद्योग को भारी टैक्स बोझ में कोई राहत नहीं दी गई है. मंदी के कारण स्वर्ण एवं हीरा कारीगरों के रोजगार जा रहे हैं. ना तो बजट में सोना-चांदी पर आयात शुल्क घटाया गया है और ना ही आभूषणों के कारीगरी शुल्क पर 18% जीएसटी पर कुछ राहत की बात की गई है. लाखों कारीगरों के रोजगार बचाने के लिए कई प्रोत्साहनों की उम्मीद थी, लेकिन वित्तमंत्री ने निराश किया है. हालांकि बैंक जमा पर बीमा गारंटी एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाना सराहनीय कदम है. इससे किसानों और मध्यमवर्गीय परिवारों की बचत सोने की बजाय अब बैंकों में जाएगी.

खत्म हो जाएगी बचत प्रोत्साहन नीति : बजाज

वाडा मैन्युफैक्चरिंग असोसिएशन के अध्यक्ष कमलनयन बजाज ने कहा कि बजट में नए टैक्स स्लैब के साथ एक पेंच भी जुड़ा हुआ है. अगर नई दरों से कर अदायगी करते हैं तो टैक्स में मिलने वाली करीब 70 रियायतों को छोड़ना पड़ेगा. पहले बीमा, निवेश, घर का रेंट, मेडिकल, बच्चों की स्कूल फीस जैसी कुल 100 रियायतें दी गई थीं जबकि अब नए टैक्स स्लैब में 70 रियायतों को खत्म कर दिया गया है. इनकम टैक्स में बड़े बदलाव के बाद टैक्स रियायतों के जरिए बचत प्रोत्साहित करने की नीति खत्म हो जाएगी. इससे बचत में गिरावट होगी और बीमा, मेडिक्लेम, छोटी बचत स्कीमों पर भी इसका असर होगा. अगर होम लोन पर टैक्स छूट भी नई स्कीम का हिस्सा होती है तो हाउसिंग भी प्रभावित होगी. छूट रियायत की वापसी के बदले कर रियायत के बाद बीमा, यूलिप, रियल एस्टेट कारोबारों का बुरा हाल होगा.

आम आदमी का ध्यान : तिवाड़ी

सीए अभिषेक तिवाड़ी ने कहा कि केंद्रीय बजट आम नागरिकों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया. अगर बैंक डूबता भी है तो आम आदमी के 5,00,000 रुपए सुरक्षित रहेंगे, ताकि आम आदमी के खून पसीने की कमाई सुरक्षित रहे.बजट में शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है. सरकार द्वारा विवाद से विश्वास स्कीम में लोगों को राहत दी गई है जिससे लोगों को ब्याज और दंड राशि में छूट दी जा सकेगी.

देश के विकास को बल देने वाला : शर्मा

सीए राधेश्याम शर्मा ने कहा कि वित्तमंत्री ने मिला-जुला बजट पेश किया है जिसमें किसान, महिलाएं और ग्रामीण नागरिकों को ज्यादा महत्व दिया गया है. टैक्स ऑडिट सेक्शन 44 एबी के तहत 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर के ऊपर होगी, ताकि देश के छोटे बिजनेस क्लास को काफी राहत मिले. बजट देश के विकास को बल देने वाला है.

बचत को हतोत्साहित करने वाला बजट :लोहिया

भारत मर्चन्ट्स चेंबर के अध्यक्ष विजय कुमार लोहिया ने कहा कि आम बजट ने कपड़ा उद्योग एवं आम आदमी को निराश किया है. टेक्सटाइल मिशन के तहत मात्र 1,480 करोड़ रु. दिए हैं, जो कि उम्मीद से काफी कम हैं. पहले ही TUFF स्कीम में मंजूर की गई रकम नही मिल रही है. बैंकों की डूबती हुई स्थिति को देखते हुए जमा राशि का बीमा 5 लाख करना स्वागत योग्य है, लेकिन आयकर की वर्तमान दरो मे कोई परिवर्तन न कर एक नए स्लेब को लाया गया है, जिसमे किसी भी तरह की छूट का लाभ करदाता को नही मिलेगा. अगर इसे दोनों स्लैब से चेक करे तो बचत को हतोत्साहित किया गया है.

एलआईसी को बेचने का निर्णय शर्मनाक :भंडारी

विलेपार्ले मार्बल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी ने कहा कि बजट में इनकम टैक्स में छूट से लेकर हर बात में छलावा हैं. आम भारतीय जनमानस में हर आदमी के लिए एलआईसी ने हमेशा एक डूबते हुए के लिए तिनके का सहारा बनने का भरोसा क़ायम किया है. 'जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी' जैसा स्लोगन देने वाली एलआईसी ने 64 वर्षों में अपने किए हुए हर वादे को पूरा करते हुए हर आम और ख़ास का दिल जीता है, लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद अब बीजेपी सरकार इसका एक बड़ा हिस्सा बेचने जा रही है, जो शर्मनाक है. पूरे बजट में बैंक जमा को लेकर सरकार की गारंटी, जो एक लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गयी हैं. उसके अलावा कुछ भी राहत नहीं हैं.

3 वर्षों में 200 अरब लीटर पानी बचाया

'अवना' की युवा CEO मैथिली अप्पलवार ने दी जानकारी

संवाददाता

पुणे. किसानों को मात्र पानी की बचत का संदेश ही नहीं दिया, बल्कि उसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराकर उन्हें स्वयं-सहायक बनाने का कार्य महाराष्ट्र व राजस्थान के विभिन्न जिलों में हमने किया. हमने 3 वर्षों में 200 अरब लीटर पानी की बचत की. यह जानकारी एम्बी इंडस्ट्रीज की स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट अवना की 22 वर्षीय संस्थापक सीईओ मैथिली अप्पलवार ने दी. मैथिली ने बताया कि बहुलक प्रसंस्करण (पॉलीमर प्रोसेसिंग) क्षेत्र की एम्बी कंपनी पैकेजिंग, एग्रो पॉलीमर व जल संरक्षण सहित चार वर्टिकल्स में कार्यरत है. 57 देशों को यह कंपनी उत्पाद निर्यात कर रही है.

गरीबी हटाना उद्देश्य

उन्होंने बताया कि कृषि व कृषकों के मसले आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए हल कर उन्हें गरीबी से उबारना हमारा उद्देश्य है. इसके लिए हम महाराष्ट्र व राजस्थान सरकार के साथ कार्य कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी सरकार ने भी इस साल पानी की बचत का महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया है और हमारा काम इसे ताकत देने वाला है.

एक पैसा प्रति लीटर खर्च

- सिर्फ ढाई लाख रुपये में 40-50 लाख लीटर पानी 5 साल तक स्टोर रखने वाले हमारे उत्पाद हैं तथा जल-संचय हेतु सिर्फ एक पैसा प्रति लीटर खर्च आता है.
- उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में पुणे के अलावा अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड़, सोलापुर, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, जलगांव, बुलढाना, धुलिया, वाशिम, हिंगोली व नासिक तथा राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर व भीलवाड़ा में कुल मिलाकर 200 अरब (बिलियन), लीटर पानी बचाया गया.
- उन्होंने बताया कि फिश फ्रेंडली पॉण हमारी नई टेक्नोलॉजी है और फिलहाल इसका परीक्षण चल रहा है. यह अगस्त महीने में बाजार में लाई जाएगी.
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर हमने पानी का 30 प्रतिशत इस्तेमाल कम करने की तकनीक भी विकसित की है. कंपनी के पास 15 पेटेंट हैं.
- रिलायंस इंडस्ट्रीज के सहयोगी ने प्रोडक्ट विकसित किया है. वेयर हाउस में चूहों व घूसों का उत्पात रोकने के लिए रोडेंट रिपेलंट खास प्लास्टिक बनाया गया है.

17% बढ़ा एम्बी इंडस्ट्रीज का लाभ

मुंबई, व्या.प्र. देश में किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए अभिनव जल संरक्षण समाधान 'एम्बी जलसंचय' तथा कृषि सुरक्षा समाधान 'एम्बी कृषिरक्षक' पेश करने वाली कंपनी एम्बी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2018-19 में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने कारोबार में 13% तथा शुद्ध लाभ में 17% की बढ़ोत्तरी दर्ज की है. 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में एम्बी इंडस्ट्रीज का कुल कारोबार 279 करोड़ से बढ़कर 315 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया. जिस पर शुद्ध लाभ 15.2 करोड़ से बढ़कर 17.8 करोड़ रुपए हो गया. एम्बी इंडस्ट्रीज की वार्षिक ईपीएस (प्रति शेयर आय) बढ़कर 10 रुपए हो गई. कंपनी को बीते वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में 83 करोड़ के कारोबार पर 4.8 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ.

एम्बी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शुद्ध लाभ 18 प्रतिशत बढ़ा

मुंबई। एम्बी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष में कुल राजस्व वित्त वर्ष 18 के 278.98 करोड़ रूपये की तुलना में 12.85 प्रतिशत बढ़कर 314.84 करोड़ रूपये हो गया है। वित्त वर्ष 19 में कंपनी के शुद्ध लाभ 16.57 प्रतिशत बढ़कर 17.79 करोड़ रूपये पहुच गया है जो वित्त वर्ष 18 में 15.26 करोड़ रूपये था।

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष 2018-19 के चौथी तिमाही में कंपनी के कुल राजस्व वित्त वर्ष 18 के 75.47 करोड़ रूपये की तुलना में 9.52 प्रतिशत बढ़कर 82.66 करोड़ रूपये रह गया है।

वित्त वर्ष 2018-19 के चौथी तिमाही में कंपनी के शुद्ध लाभ 18.50 प्रतिशत बढ़कर 4.81 करोड़ रूपये पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के समान तिमाही में 4.06 करोड़ रूपये था।